भा.क.नि

CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड,

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय, कपास भवन, प्लॉट नं.3/ए, सेक्टर-10, सीबीडी बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614, फैक्स नं. 27576030, 27579219, 27576069,
टेली.नं. 022- 27579217, ई-मेल/E-mail: headoffice@cotcorp.com

प्रेस विज्ञप्ति

निगम का शुद्ध लाभ 45% बढ़ा

सीसीआई के कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

भारतीय कपास निगम की 20 अगस्त, 2008 को मुंबई में आयोजित 38 वीं वार्षिक सामान्य बैठक

भारत विश्व में कपास का दूसरा बड़ा उत्पादक देश बना :

* देश में कपास उत्पादन कपास मौसम 2007-08 के दौरान 315 लाख गॉठों के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया जबकि वर्ष 2006-07 में यह 280 लाख गॉठें था । इसके साथ ही भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा बड़ा कपास उत्पादक देश बन गया है, जिसने संयुक्त राष्ट्र अमरीका को तीसरे स्थान पर पहुँचा दिया है ।

कपास के बुआई क्षेत्र में वृद्धि:

* वर्ष 2007-08 के दौरान कपास खेती के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 4% वृद्धि के साथ 95.55 लाख हेक्टर्स हो गया है, जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान यह 91.44 लाख हेक्टर्स था ।

उत्पादकता में वृद्धि :

* संपूर्ण देश में हायब्रिड/बीटी बीजों के व्यापक उपयोग तथा खेती की बेहतर और संशोधित तकनीकी को अपनाने के लिए कपास किसानों की दृष्टिकोण में आये परिवर्तन से कपास की औसत उत्पादकता लगभग 7% बढ़कर 560 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर पहुँच गयी है, जो पिछले वर्ष 521 कि.ग्रा. थी ।

उच्चतर रूई मूल्य

* वर्ष 2007-08 में रूई के आरंभिक मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 17% तक ऊँचे रहे हैं, तथापि निर्यात में लगातार मांग को देखते हुए रूई के मूल्य बढ़ते रहे । अक्तूबर, 2007 के अंत से जुलाई, 2008 तक रूई के मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 20% से 40% तक ऊँचे रहे ।

वर्ष 2007-08 के दौरान रिकार्ड रूई निर्यात :

* रूई सलाहकार बोर्ड ने देश से कपास निर्यात का आकलन 85.00 लाख गॉठें किया है और निगम ने निर्यात में 1.73 लाख गॉठें बेची हैं ।

रूई का आयात

* पिछले वर्ष के अनुसार, देश में रूई का आयात पुन: एक बार मुख्यत: अतिरिक्त लंबे तंतु की रूई तक सीमित रहा, जिसकी कम आपूर्ति होने के कारण लगभग 6.50 लाख गॉठों का आयात हुआ, जिसमें मिलों द्वारा संविदा की गयी अतिरिक्त लंबे तंतु की किस्मों की लगभग 2 लाख गॉठें भी शामिल हैं ।

सीसीआई द्वारा लगातार चौथे वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद

* निगम ने सौंपी गयी भूमिका के अनुसार, लगातार चौथे वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद का कार्य किया है तथा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 11.88 लाख क्विंटल कपास खरीदी, जो 248.64 करोड़ रूपये मूल्य की 2.25 लाख गॉठों के समकक्ष है, ताकि इन राज्यों के कपास उत्पादकों को पारिश्रमिक मूल्य का भुगतान सुनिश्चित हो सके । वर्ष के दौरान एमएसपी कार्य की गहनता पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है ।

सीसीआई द्वारा उच्चतर वाणिज्यिक खरीद

* न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद के अलावा, निगम ने प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक खरीद कार्य भी किया और 921.34 करोड़ रूपये मूल्य की 7.65 लाख गॉठें खरीदीं, जबकि पिछले वर्ष 286.35 करोड़ रूपये मूल्य की 2.71 लाख गॉठें खरीदी गयी थीं ।

1637 करोड़ रूपये का बिक्री टर्न-ओवर

* समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीधे उपभोक्ता मिलों को बेचने की आक्रमक बिक्री नीति से गुणवत्तावाली रूई की आपूर्ति करते हुए और बिक्री से पहले और बाद में बेहतर सेवाएँ देते हुए तथा रूई के विदेशी बाजारों में बिक्री के सघन प्रयत्नों के कारण निगम पिछले वर्ष के 1786.67 करोड़ रूपये की तुलना में 1636.83 करोड़ रूपये का टर्न-ओवर प्राप्त कर सका है । टर्न-ओवर में घटौती का मुख्य कारण निर्यात में घटा हुआ पोतवहन, 1 अप्रैल, 2007 को घटा हुआ आरंभिक स्टॉक तथा मिलों द्वारा सीएसटी के घटने की आशा में गॉठों का धीमा उठाव था ।

वर्ष 2007-08 में सीसीआई के लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि

* देशी और निर्यात बिक्री दोनों में निजी व्यापारियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद, निगम वर्ष 2007-08 में 22.55 करोड़ रूपये (कर के बाद) का लाभ प्राप्त कर सका है, जबकि वर्ष 2006-07 में 15.51 करोड़ रूपये (कर के बाद) का लाभ था, इस प्रकार पिछले वर्ष से लगभग 45% वृद्धि दिखायी है ।

भारत सरकार को लाभांश का निरंतर भुगतान

* निगम के लगातार अच्छे कार्य-निष्पादन को देखते हुए, निगम ने भारत सरकार को 2500 लाख रूपये की शेयर पूँजी पर 20% की दर से कुल 584.98 लाख रूपये (लाभांश पर कर सहित) का लाभांश घोषित किया है, जो पिछले वर्ष के अनुसार है ।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यान्वयन:

* निगम कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन III और IV के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी का कार्य करता रहा और वर्ष के दौरान, मिनी मिशन III के अंतर्गत 28 मार्केट याड्‌र्स को विकास के लिए लिया गया, जिसकी कुल परियोजना लागत 60.93 करोड़ रूपये है और मिनी मिशन IV के अंतर्गत 180 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों को आधुनिकीकरण के लिए लिया गया, जिसकी कुल परियोजना लागत 318.72 करोड़ रूपये है ।

मिनी मिशन II के अंतर्गत फ्रन्ट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन:

* मिनी मिशन II के अंतर्गत फ्रन्ट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में निगम ने 4400 से अधिक एफएलडीज उत्पादन प्रौद्योगिकी पर तथा 2 एफएलडीज आयपीएम पर, वर्ष 2007-08 के दौरान सभी मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में सफलतापूर्वक आयोजित की हैं, जिसमें निगम की सभी शाखाओं को शामिल किया गया है ।

सघनित कपास खेती (संविदा खेती):

* वर्ष 2007-08 के दौरान निगम ने सघनित कपास खेती (संविदा खेती) की संकल्पना को प्रोन्नत करने और लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न जारी रखे । इस कार्यक्रम का विस्तार सभी कपास उत्पादक राज्यों में अपने शाखा कार्यालयों तथा अग्रणी वस्त्र मिलों को सहयोगी बनाते हुए लगभग 40,044 हेक्टर क्षेत्र में किया गया ।

****